

संकेत 74,529.08
▼ 329.81

निफ्टी 23,329
▼ 85.30

रोना 1,54,900
प्रति दस घंटा
▼ 1,500

गोल्ड 2,42,000
प्रति दस घंटा
▼ 20

डॉलर ₹ 95.62
प्रति दस घंटा
▼ 0.18

रुपया ₹ 98.66
प्रति दस घंटा
▼ 0.18

खाड़ी संकट ने खोले पेट्रो निर्यात के नए दरवाजे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : होमजुग और खाड़ी क्षेत्र की रिफाइनरी क्षमता पर दबाव के बीच भारत को कच्चे तेल आयात की लोकर जिता बनी हुई है। हालांकि, यही संकट भारतीय रिफाइनरी के लिए पेट्रोलिएम उत्पादों के निर्यात का नया दरवाजा खोल रहा है। पारंपरिक निर्यात मार्गों के बाधित होने के बाद कई देशों ने पेट्रोल और डीजल की खरीद भारत से शुरू कर दी है। अप्रैल-अप्रैल 2026 में भारत के पेट्रोलिएम उत्पाद निर्यात में सालाना आयात पर करीब 46 प्रतिशत की तेजी आई है। पिछले एक हफ्ते में सस्ती अरब और रूस के प्रमुख रिफाइनरीयों पर हमले के बाद भारत से पेट्रोल, डीजल और दूसरे उत्पादों का निर्यात और बढ़ने के आसार हैं।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक केन्या में भारत यूईए और सऊदी अरब को पीछे छोड़कर पेट्रोलिएम उत्पादों का सबसे बड़ा आयातकर्ता बन गया है। मोनोबिक और अन्य पूर्वी

- पारंपरिक निर्यात मार्गों के बाधित होने के बाद कई देशों ने पेट्रोल और डीजल की खरीद भारत से शुरू की
- भारत के साथ कूटनीतिक संबंध अच्छे नहीं होने के बावजूद यूईए भारतीय पेट्रो उत्पादों का नया खरीदार बना



तेजी से बढ़ रही भारत की रिफाइनिंग क्षमता

देश में 23 वार्षिक रिफाइनरी की कुल स्थापित क्षमता अब 26.7 करोड़ टन प्रति वर्ष के आसपास पहुंच गई है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक इसे 30-31 करोड़ टन और तब समय में 45 करोड़ टन तक पहुंचाना का है। इंडियन आयल की पानीपत, कोयली, बरनी और पारानी रिफाइनरीयों की विस्तार परियोजनाएं 2026 के अंत तक शुरू होंगी हैं। नुमातीबाद रिफाइनरी की क्षमता 80 लाख टन से बढ़कर 90 लाख टन करने का काम 2027 को शुरूआत में पूरा होने की उम्मीद है। राजस्थान में एचपीसीएल की नई रिफाइनरी पहले ही चालू हो चुकी है, जबकि अगले प्रवेश में बीपीसीएल की नई सोनीपत परियोजना पर काम आगे बढ़ रहा है।

बाजारों जैसे यूईए और अमेरिका में पेट्रोल घटा है, लेकिन नए गंतव्यों ने इसकी भरपाई कर दी है। हेल्लिंको स्थित सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी (एसआईएन) को रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने अप्रैल में 1.72 लाख टन तेल उत्पाद आयात किया, जिसकी कीमत करीब 11.4 करोड़ रुपये थी। इनमें से 70 प्रतिशत भारत से आयात किया गया था। यह उत्पाद गुजरात की नवरा एनर्जी की बांडीन-अमरावती से लाया, मिथ के जमिना लाइसेंस जौन में जाइस-जे-जाल स्थानीयता हुआ और फिर रूस के आर्थिक बेरगाह बेलेगो मोरे पहुंचा। बालीज मंत्रालय का डाटा बताता है कि अप्रैल-अप्रैल, 2026 में पेट्रो उत्पादों का निर्यात 35.31 अरब डॉलर रहा है और यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 39.43 प्रतिशत ज्यादा है। अकेले अगस्त में पेट्रोलिएम उत्पादों का निर्यात 63.27 प्रतिशत बढ़कर 6.81 अरब डॉलर का हो गया है।

खरीदने चाहता है। भारत और यूईए की मांग तेजी से बढ़ी है। पेट्रोलिएम मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका का तेल सस्ता हर देश आज भारत से डीजल

चीन से ग्लाईसिन के आयात की डीपिंग-रोधी जांच शुरू

नई दिल्ली : भारत ने चीन से ग्लाईसिन के आयात के खिलाफ डीपिंग-रोधी जांच शुरू की है। ग्लाईसिन का इस्तेमाल स्टाइल बढने वाले पदार्थों के रूप में और दवा उद्योग में एक घटक के तौर पर किया जाता है। डीपिंग-रोधी जांच कि यह जांच परतु विनिर्माण पदार्थ आनिमस की शिवायत पर शुरू की गई है। (कंपनी ने आरोप लगाया है कि चीन से ड्रा किए जाने वाले आयात से उसे गंभीर नुकसान हो रहा है।) कंपनी ने इन आयात पर डीपिंग-रोधी शुरू लगाने का अनुरोध किया है। (B2)

अमेरिकी बाढ़ पीड़ितों के बुद्धि और खाद्य वस्तुओं की

कीमती में बुद्धि से बचाई के दबाव के चारों ओर आइड खाद्य वस्तु बढने के लिए मजबूर हो सकता है।

— समुद्री मत्स्य, मुख्य अफेयर्स, डेमाइ



आट नए संयंत्रों से घटेगी यूरिया की आयात निर्भरता

अटि: हर्मा • जागरण

नई दिल्ली : उर्वरकों की जरूरत पूरी करने के लिए आट नए यूरिया संयंत्र लगाने की तैयारी है। इनकर करीब 80 हजार करोड़ रुपये निवेश होगा। संयंत्रों के चालू होने पर देश में सालाना करीब एक करोड़ टन अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन होने लगेगा। इससे बड़ा फायदा यह होगा कि यूरिया का बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार होने लगेगा।

जुलाई में राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 की मंजूरी मिलने के बाद सरकार के पास नए संयंत्र लगाने के लिए 14 प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से आठ को अगले एक-दो महीने में मंजूरी मिल सकती है। हालांकि उत्पादन शुरू शुरू नहीं हो पाया। प्लांट लगाने एवं चालू करने की प्रक्रिया में चार से पांच वर्ष लग सकते हैं। अभी देश में प्रत्येक वर्ष करीब सौ सौ लाख टन उर्वरकों की जरूरत होती है। इनमें चार सौ लाख टन निर्यात यूरिया है। रफिन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार



- नई यूरिया निवेश नीति की मंजूरी के बाद केंद्र को मिले 14 प्रस्ताव
- इनमें से आठ को अगले एक से दो महीने में मिल सकती है मंजूरी

2025-26 में देश में 293.26 लाख टन यूरिया का उत्पादन हुआ था एवं 103.50 लाख टन आयात करने पड़ा। नए संयंत्रों से इस अंतर को कम किया जा सकेगा। यूरिया का घरेलू उत्पादन बढ़ने के लिए देश में एक दशक में छह संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इनमें रमागुडम, गोखपुर, सिंदरी और बरनी के संयंत्र तथा निजी क्षेत्र के दो संयंत्र शामिल हैं। इनसे कुल 76.2 लाख टन सालाना उत्पादन हो रहा है। फिर भी आयात खत्म नहीं हो सका है।

यूरिया के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भरता के कारण कहीं देश में संकट पैदा होने पर भारत

में यूरिया महंगी हो जाती है। मई में भारत की 947 लाख टन प्रति टन की दर से यूरिया आयात करने पड़ा है। बाद में कोमत घटकर करीब 406 डॉलर प्रति टन रह गई।

यूशा के साथ गंधी जी जरूरी: यूरिया बनाने के लिए एस गंधी जी की जो भारत के लिए बड़ी चुनौती है। इसीलिए यूरिया के अत्यधिक उत्पादन के साथ एस की जरूरत भी बढ़ेगी। यह एस महंगी हुई तो लागत भी बढ़ सकता है।

यूरिया के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भरता के कारण कहीं देश में संकट पैदा होने पर भारत

इन कंपनियों के प्रस्ताव पर विचार कर रही सरकार

रफायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक, जिन कंपनियों के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, उनमें से उत्तर प्रदेश से है। गोरखपुर में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रफायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की दूसरी इकाई और शाहजहापुर में गुजरात पेट्रोलाइजर्स लिमिटेड (केएफएएल) प्रस्ताव है। गेल के दो प्रस्तावों के एक महानगर एवं दूसरा छतरीसराइ के राजनाथगंधी में है। यवत परितोरासरी एड केमिकल्स लिमिटेड, मीटयस लिमिटेड और मद्रास पेट्रोइंडस्ट्रीज लिमिटेड के भी एक-एक प्रस्ताव है। गेल और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड पेट्रोइंडस्ट्रीज के प्रस्तावों में 12.7 लाख टन सालाना क्षमता का एक नया एस आवासीय यूरिया संयंत्र लगाने के लिए हाल में ही समझौता किया है।



क्लिक करें ये जुड़ी खबरें और आर्टिकल के लिए खोजें करें या जागरण.com

एक नजर में

अदानी की पांच कंपनियों ने सेबी से विवाद निपटारा

नई दिल्ली : कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने मंगलवार को अदानी समूह की पांच कंपनियों के खिलाफ 'रिलेटेड-पार्टी ट्रांजैक्शन' (अदानी ग्रुप-सेबी) की जानकारी देने से जुड़े नियमों के कांफिट उल्लंघन के मामले को निपटार कर दिया। इन कंपनियों ने निपटार के लिए कुल 1.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह कांफिट इंडियन रिस्क की रिपोर्ट में उद्योग की और कारपोरेट गवर्नंस से जुड़े मुद्दों की सीरी ब्राग की नई किंवदंती के बाद शुरू हुई थी। इसमें लिफ्टिंग निगमों और पहले के लिफ्टिंग समझौता का निपटारा उल्लंघन भी शामिल था।

बीते वर्ष सैमसंग इंडिया का लाभ 36 प्रतिशत घटा

नई दिल्ली : बीते वर्ष 2025-26 में सैमसंग इंडिया का लाभ 36 प्रतिशत घटकर 7,228.10 करोड़ रुपये रहा है। विजिओ इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी सैमसंग इंडिया में यह जानकारी दी है। हालांकि, राजस्व 1.2 प्रतिशत की मामूली बुद्धि के साथ 1.12 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। बीते वित्त वर्ष में कंपनी का मोबाइल फोन और एप्लेसरीज का राजस्व 1.35 प्रतिशत घटकर 14,471.2 करोड़ रुपये रहा है। (B2)

रुपया 16 पैसे की बढ़त के साथ 95.62 प्रति डॉलर पर मुहूर्त

मुंबई : कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और अमेरिकी डॉलर पर जोर देने की वजहों से रुपया मालावार के 16 पैसे मजबूत होकर 95.62 प्रति डॉलर पर रहा। विश्वी मुद्रा बाजारों में पड़ाने कि ईरान के सात दिन के भीतर होमजुग जलजलकृत खोले की खराब के बाद डेट कब्जे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई। खराब में सहा गया था कि अगर अमेरिकन वरराइली की नोबेलटी हटाते हैं और ईरान पर सैन्य दबाव कम करता है तो ईरान मुहूर्त जलजलकृत खोले सहा है। (B2)

जीएसटी सुधारों से खपत के साथ कर संग्रह भी बढ़ा

जीएसटी 2.0 का एक साल पूरा, 12 और 28 प्रतिशत की कर दरों को किया गया था समाप्त

राष्ट्रीय गुजरात • जागरण

क्या-क्या बदला...

- नई दिल्ली : पिछले साल 22 सितंबर को जीएसटी कार्डिनल की 56वीं बैठक के फैसले को लागू किया गया तो जीएसटी संशोधन में निगवत की आंशिकता संशोधन की गई। दरों के 12 और 28 प्रतिशत के संस्तर को समाप्त कर दिया गया था। 22 सितंबर पर से जुड़े कर्मोबाह समी उत्पन्न की पांच तो वहीं 28 प्रतिशत के ब्रेकेट में आने वाले उत्पादों की 18 में शामिल कर दिया गया था। ऐसे में आंशिकता का डाटा थो कि इससे कर संशोधन में निगवत आया। हालांकि, कर्मोबाह के दाम कम होने से खपत बढ़ गई, जिससे जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया। केंद्र और राज्य के राजस्व में इनके के साथ न्यूट्रैलिजिंग को बढ़ा मिला और राजस्व को समर्थन मिला। आंकड़े भी यही कह रहे हैं। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले



लोगों की आंशिकता के विपरीत जीएसटी दरों में कटौती के बाद भी कलेक्शन घटा गया। यद्यपि योक्ति सस्ती होने से खपत में बढ़ोतरी हुई। इससे अर्थव्यवस्था को राहत पहुंचने में मदद मिली है। एसएचएम, आवाह का विशेषज्ञ और एडवो, इलाहा

पांच महीने में जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। जिसलिए का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले 12-13 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। जीएसटी कलेक्शन बढ़ने से केंद्र के साथ राज्यों के

राजस्व में भी इजाजत दिख रहा है। जिसलिए का अनुमान है कि मजबूत जीएसटी कलेक्शन की वजह से देश के 18 प्रमुख राज्यों का सकल राजस्व घरेलू उत्पाद (जीएसटीपी) में 9-11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। जीएसटी कटौती का सबसे अधिक असर आटोमोबाइल उद्योग

जीएसटी 3.0 में पेट्रोल-डीजल को कर दायरे में लाने की चर्चा

विशेषज्ञ और जीएसटी 3.0 की चर्चा करने लगे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध व पश्चिम यूरोप के पेट्रोल की दरोहें द्वारा जीएसटी 3.0 में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल करना के खाब राजस्व पर पड़ सकता है। हालांकि जानकारी का कहना है कि इस काम में चर्चा से कम एक साल का समय लग सकता है और इसके लिए राज्यों की मंजूरी जरूरी है।

हेल्थ इश्योरेंस खरीदने वालों को नहीं मिला लाभ

जीएसटी कटौती से हेल्थ और लाइफ इश्योरेंस खरीदने वाले ग्राहकों की फायदा मिलने की उम्मीद थी। लेकिन कोमिती ने लाभ नहीं दिया। जीएसटी 2.0 में हेल्थ और लाइफ इश्योरेंस पर 18 प्रतिशत जीएसटी को रद्द कर दिया गया। लेकिन हेल्थ इश्योरेंस देने वाली कोमिती ने जीएसटी समाप्त होने के बाद हिस्सेदारी में प्रीमियम की 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ा दिया।

पर देखा गया। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी महारि सुजुकी को चालू वित्त वर्ष में अपने पैरिज कार की बिक्री में 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है। आटोमोबाइल कोमिती के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 11 महीने में देश में पेट्रोल की बिक्री में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

अवधि के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है। जीएसटी कटौती की वजह से कंज्यूमर गुड्स की बिक्री में इस साल जनवरी-मार्च विमाही में ज्यादा अंक में बढ़ोतरी दिखी, लेकिन बाद में कच्चे माल की कीमतों में तेजी से कंज्यूमर गुड्स के दाम बढ़ने लगे जिससे इनकी बिक्री पर भी असर देख गया।

अगले एक दशक में तीन गुना हो जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था

मुंबई, आइएनएस: जेपी मॉर्गन पेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेपी हिमन ने कहा है कि अगले दस सालों में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग तीन गुना हो जाएगा। ओरिजिनेल इन्वेंस्टमेंट बैंक ने भारत और अमेरिका से जल्द रफायन यूएन टायपर समझौते की अंतिम रूप देने की भी अपील की। हिमन ने यह भी बताया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई शहरों (जैसे लुगातार महेश, सारकी उद्योग में बढ़ोती, ध-राजनीतिक तनाव और पूंजी की बढ़ती मांग) का सामना करना पड़ रहा है। उनका अनुमान है कि ब्राल टेल और बॉट पर रिटर्न लॉरे समेत ऊर्जा बने रह सकते हैं। हिमन ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़ा प्रोड्यूसर पूंजी की मांग को और बढ़ा सकते हैं और इसके और बढ़ने की संभावना संचय से कहीं ज्यादा होगी।

मजबूत वृद्धि परिदृश्य के मामले में भारत सबसे आगे: डब्ल्यूईएफ

नई दिल्ली, ईए: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत दुनियाभर में सबसे मजबूत वृद्धि परिदृश्य के मामले में सबसे आगे है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अच्छे कारोबारी माहौल की बात करें तो चीने नंबर पर आता है। इस साल मई में डब्ल्यूईएफ प्रकाशित किए गए मुख्य आर्थिक सालाहकारों में 98 प्रतिशत ने कहा कि डब्ल्यूईएफ के आउटलुक सर्वे में भारत दूसरे नंबर पर था। ताजा सर्वे में पाया गया कि 56 प्रतिशत मुख्य आर्थिक सालाहकारों की उम्मीद है कि वैश्विक परिदृश्य स्थिर रहेगा या बेहतर होगा। मई में 89 प्रतिशत ने हालात के कमजोर होने की उम्मीद की थी। डब्ल्यूईएफ के अनुसार भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अच्छे कारोबारी माहौल की बात करें तो अमेरिका सबसे आगे है, उसके बाद दक्षिण-पूर्व एशिया और यूरोप का नंबर आता है।

चार साल के उच्च स्तर पर स्टील की कीमतें

नई दिल्ली, ईए: मार्गो कच्चे माल (कोकन) की मांग और मानसून के बाद की मांग में वृद्धि के कारण धीरे-धीरे स्टील की कीमतें चाल साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। मार्केट रिजर्च फर्म ग्लोबल का का कहना है कि कीमतों में वृद्धि का यह स्तर चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में जारी रुने की उम्मीद है। बिजनेस के आंकड़ों के अनुसार, हाट स्टील (एचएसटी) और कोल्ड रोलड स्टील (सीएसटी) इस समय 64 हजार रुपये और 75 हजार रुपये प्रति टन पर कारोबार कर रहे हैं। इससे पहले जून 2022 में यह रेटों की उच्चतम स्तर पर पहुंचे थे। एचएसटी के अंतरासी वैश्विक स्तर पर उपयोग किए जाने वाले स्टील उत्पाद हैं। एक अगस्त से अब तक एचएसटी की कीमतें में क्रमशः छह हजार और 8,500 रुपये प्रति टन की वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्री सीतारमण की अपील, हर असहमति को कोर्ट में ले जाने से बचे उद्योग जगत

नई दिल्ली, ईए: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को उद्योग जगत से कहा कि वे हर असहमति को कोर्ट में ले जाने से बचे और कारपोरेट गवर्नंस मैकेनिज्म को मजबूत करने पर ध्यान दें। उन्होंने यह बात पर जोर देते हुए कहा कि अग्रा कागजात गवर्नंस सिफ्ट अगुवाई देने वाली प्रक्रिया नहीं है बल्कि वह मानक है जो उद्योग अपने लिए हर करते हैं।

एचएसएमए पर एक समारोह को संबोधित करती हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार के बीच परेसे की मांग नहीं की जा सकती है बल्कि इसका आगो सामन्य से निर्माण करना होगा। उद्योग जगत को सरकार और नियामक के साथ सहकार्य करके से जुड़ना चाहिए। कानून मदद देने वाला उपलब्ध रहेगा

वित्त मंत्री ने कहा-आपसी समझ से भारोस का निर्माण करना होगा

उद्योग जगत सरकार और नियामक से सहकार्य करके से जुड़े

मेड इन इंडिया से इमेजिन इन इंडिया की ओर बढ़ें

सीतारमण ने कहा, मेड इन इंडिया से अब इमेजिन इन इंडिया प्रोड्रक्ट की ओर बढ़ना चाहिए। हर उद्योगों की परिकल्पना यथानुर स्तर पर कर्नी चाहिए, फिर उन्हें डिजाइन कर एटोमेल को ही ब्रह्मांड से देना है ही विशिष्टता का दुनियाभर के बाजार में उन्हे बेचना जाए। आउटसोर्डी पर भारता का सकल उद्योग 0.83 प्रतिशत है जो आईसीडी के 2.7 प्रतिशत, चीन के 2.6 प्रतिशत और अमेरिका के 3.5 प्रतिशत से बहुत कम है।

लेकिन हर असहमति मुकदमेबाजी में नहीं बदलनी चाहिए। मतभेदों के विवाद करने से पहले सामान्यता की दिशा में काम करना लाभाज्य होगा। सीतारमण ने उद्योग जगत से कहा कि वे ज्यादा मजबूत और बेहतर गवर्नंस वाली कंपनियों के निर्माण में रुचि लें, क्योंकि

देश 2047 तक विश्वसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। भारत को बड़ का अगला चरण गुणवत्ता पर आधारित होगा और ऐसे में उद्योग जगत को रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। इससे मौजूदा उत्पादों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

देश 2047 तक विश्वसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। भारत को बड़ का अगला चरण गुणवत्ता पर आधारित होगा और ऐसे में उद्योग जगत को रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। इससे मौजूदा उत्पादों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय फलक

वैश्विक मांग- आपूर्ति से तय होती हैं चीनी की कीमतें : गडकरी

नई दिल्ली, आइएनएस: देश में चीन की खुदरा कीमतों में वृद्धि के बीच केंद्रीय सहक परिवहन और राजमार्ग की निमित्त गडकरी ने मंगलवार को कहा कि चीनी की कीमतों वैश्विक मांग- आपूर्ति से तय होती हैं। कृषि उत्पादों की तैयार करने में सरकार की भूमिका बहुत कम होती है।

नेशनल फेडरेशन आफ कोऑपरेटिव फूड प्रोड्यूसर्स लिमिटेड (एफएनएसपीएफएल) के कांफ्रेंस में गडकरी ने कहा, हम अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में चाल कर रहे हैं। उद्योगों की कीमतें निर्धारित नहीं कर सकतीं। चीनी की कीमतें ब्राजील जैसे देशों में उत्पादन से काफी प्रभावित होती हैं, जबकि अन्य बसुएँ भी वैश्विक बाजार द्वारा प्रभावित होती हैं। ब्राजील बड़े पैमाने पर मशीनों से चीनी वाली खेती से लाभान्वित होता है, जो उत्पादन

नई दिल्ली, ईए: बकर स्टाक से 35 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज बेचने के सरकार के उद्योगों के बावजूद बढ़े हुए हैं प्याज अब भी रुला रहा है। मंगलवार को मेट्रो शहरों के खुदरा बाजारों में प्याज की कीमत 58 रुपये से 60 रुपये प्रति किलो की बढ़ी थी।

उधोभोता मांग से मंत्रालय के डाटा के अनुसार दिल्ली में प्याज 53 रुपये प्रति किलो की दर से बिका, जबकि मुंबई में प्याज की कीमत 58 रुपये प्रति किलो रही। कोलकाता और चेन्नई में प्याज का मूल्य 60 रुपये प्रति किलो रहा। 22 सितंबर को देश में प्याज की खुदरा औसत कीमत 54.2 रुपये प्रति किलोग्राम रही। प्याज की अधिकतम कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम, जबकि न्यूनतम कीमत 29 रुपये प्रति

35 रुपये प्रति किग्रा की रियायती दर से प्याज बाजारों की सरकार की कोशिशों के बावजूद नहीं मिल रहे रहत

मेट्रो शहरों के खुदरा बाजारों में 53 से 60 रुपये प्रति किग्रा प्याज की कीमत

किलोग्राम रही। हालांकि प्रत्येक ट्रेड डेटा के मुताबिक खुदरा कीमतें मंत्रालय के डाटा की तुलना में काफी ज्यादा थीं। गौतमलाल है कि प्याज की कीमतों के लिए लागू होने के लिए सरकार दिल्ली और देशभर के 50 से अधिक अन्य शहरों में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बाबर स्टाक से सस्ती वाली कीमतों के जरिये आपूर्ति बढ़ा रही है। कोर्ट एक्सप्रेस नमक खास ट्रेन के साथ सहक मार्ग से भी प्याज उत्पादक राज्यों से अत्यंत पहुंचाना जा रहा है।



नई दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय सहक परिवहन मंत्री निमित्त गडकरी के कांफ्रेंस में राष्ट्रीय फलक

विद्यार्थियों की फिफ्ट

शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि इसमें विद्यार्थी का सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और शारीरिक विकास भी शामिल है। मगर सवाल है कि देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में क्या इन मानदंडों को अपनाकर विद्यार्थी के चहुँमुखी विकास पर ध्यान दिया जाता है? क्या सांस्थानिक स्तर पर संवेदनशील और समावेशी दृष्टिकोण के साथ हाशिये के तबकों के विद्यार्थियों की समस्याओं पर गौर किया जाता है? यह बेवजह नहीं है कि स्कूलों से लेकर उच्च संस्थानों तक में पढ़ाई, परीक्षा, करिअर और भविष्य को लेकर बढ़ता दबाव और कुछ स्तर पर उपेक्षा कई विद्यार्थियों को मानसिक तनाव की ओर धकेल रहा है। इस कारण विद्यार्थियों की आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसी के भेदनेजर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी उच्च शिक्षा संस्थानों को विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने और आत्महत्याओं की घटनाओं की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विद्यार्थियों को आत्महत्या या अपराकृतिक मौत की सूचना तत्काल पुलिस को देने और इसकी खालीना रिपोर्ट तैयार करने की भी कहा है।

इस मामले में उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा था कि उच्च शिक्षा संस्थानों में आत्महत्या की बढ़ती समस्या के पीछे शैक्षणिक दबाव, जाति आधारित भेदभाव, आर्थिक तनाव, यौन उत्पीड़न और परीक्षा में विफलता जैसे कारण शामिल हैं। सवाल है कि क्या शिक्षा संस्थान महज अंकों की प्रतिस्पर्धा के केंद्र बनकर रह गए हैं? क्या विद्यार्थियों की परेशानियों के समाधान को लेकर संस्थानों की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को हाशिये पर रखा जा रहा है? यही नहीं, आवसरी उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए चौबीसों घंटे चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के शीघ्र अंदाज के निर्देशों पर भी पूरी तरह अमल नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि शिक्षा मंत्रालय को परिपत्र के जरिए शिक्षा संस्थानों को इन निदेशों की याद दिलानी पड़ी है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में देश भर में तेरह हजार से अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न संस्थानों से आत्महत्या की। इस तरह के मामलों में वर्ष 2014 से 2023 के बीच सरत फौरन से अधिक की वृद्धि हुई है। आइए इसी वर्ष प्रसिद्धि संस्थानों में भी यह समस्या गहरी तो रही है। हाल ही में आइएआई मुंबई में एक छात्र को आत्महत्या की घटना ने एक बार फिर इस मसले पर व्यापक चर्चा और सुचारु पर तकाकों की जरूरत को रेखांकित किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2018 से 2023 के बीच देश के विभिन्न आइएआई में 39 छात्रों ने आत्महत्या की। शीघ्र न्यायालय की ओर से गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आइएआई में ज्यादातर सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए खुद को पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं मानते, क्योंकि उन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं मिला है। जिन्हें है कि समस्या केवल संस्थानों की लापरवाही या जाहिरात से मुह मोड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी स्तर पर नीतिगत निर्णयों की अनुपस्थिति भी इसका एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा, शिक्षकों की भी विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनना होगा। शिक्षक का काम केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं सहयोगी वातावरण तैयार करना भी है।

दुराग्रह की बोली

म बोलाचक के दौरान कुछ लोग अक्सर किसी व्यक्ति के रंग-रूप आदि के संबंध में ऐसी टिप्पणियां करते हैं, जिन्हें कहते और सुनने के बाद सामान्य तौर पर सहजता वनी रहती है, लेकिन उसमें कुछ शब्द या उसके भाव ऐसे हो सकते हैं, जिससे कोई एक व्यक्ति या अंशों तरह के कुछ लोग खुद को अपमानित या शर्मिंदा महसूस करें। खासतौर पर समाज के नेतृत्व वर्ग से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अपराध, भाषा और अभिव्यक्ति के मामले में सार्वजनिक तौर पर ऐसा उदाहरण सामने रखें, जिसे लोग आदर्श मानें और उससे प्रेरणा लें। मगर अफसोस की बात है कि कई बार कुछ नेता भाषण या बातचीत के दौरान बिना सोचे-समझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर बैठते हैं, जिनसे कोई व्यक्ति या समाज का एक वर्ग खुद को अपमानित महसूस करता है। सवाल है कि एक बड़े जनसमर्थन और लोगों के नेतृत्व का दावा करने वाले ऐसे लोगों को क्या सामान्य शिक्षा और भावनाओं का ख्याल रखने के बुनियादी तकाजों की भी पता नहीं होता। बेलागम तरीके से कुछ भी बोलते हुए क्या वे कभी अपने मुह से निकले शब्दों के अंतर का अंदाजा लगा पाते हैं?

गौरतलब है कि भाषण नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गत रविवार को सार्वजनिक कार्यक्रम में एक महिला पार्षद का वजन बढ़ते को लेकर विचित्र टिप्पणी कर दी, जिसकी ओर लक्ष्मी आचार्या आई। हालांकि इससे उम्मेद विवाद के तूल पकड़ने का दाव उठाने इस पर खेद जाहिर कर दिया, लेकिन सच यह है कि इस तरह किसी की शारीरिक बनावट या रंगरूप आदि को लक्ष्य करके हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी कर देना एक आम चलन रहा है। जिसके इससे एक खास तरह के पूर्वाग्रह की मानसिकता बनी-पढ़ी है, जो अपने अंतर में संवेदनशीलता और अमानवीयता को बढ़ावा देती है। कई लोग ऐसे शब्द गाहे-बगहाे दोहराते हुए उसे महज एक प्रजाक मानते-बताते हैं, लेकिन सच यह है कि उससे किसी व्यक्ति की भावनाओं को चोट पहुंचे, वह शर्मिंदा महसूस करे। समाज में प्रचलित ऐसी कई धारणाएं हैं, जो अपने मूल में किसी को अपमानित करती हैं या उसका मजाक बनाती हैं। ऐसे पूर्वाग्रहों या ऐसी मानसिकता से मुक्त होना ईसाईयत के मूल्यों का तकाज है।

कौशल की कसौटी पर भविष्य की राह

आज लाखों युवा रोजगार के लिए निकलते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनकी डिग्री और उद्योगों की वास्तविक मांग के बीच बड़ी खाई है। बदलते परिदृश्य में यह चिंता का विषय है।

रंजना मिश्रा



भारत को विश्व पटल पर सबसे युवा देश होने का गौरव हासिल है, लेकिन युवाओं की इस विशाल आबादी को वास्तविक जनसांख्यिकीय लाभार्थ में बदलना आज सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल युवा जनसंख्या के आकार से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि उस आबादी का कितना हिस्सा शिक्षित, हुनरमंद और आर्थिक रूप से उत्पाक है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट कावंबल, वर्तमान शिक्षा प्रणाली और युवाओं की जमीनी सच्चाई का चीकाने वाला आंकड़ा सामने रखती है। इसके मुताबिक, देश के पंद्रह से उन्तीस वर्ष के आयु वर्ग के लगभग पौने नौ करोड़ युवा एक ऐसी निष्क्रिय अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो न तो किसी औद्योगिक शिक्षा का हिस्सा हैं, न किसी प्रकार के रोजगार से जुड़े हैं और न ही भविष्य के लिए कोई विश्वव्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह आंकड़ा देश की उस विप्लान ऊर्जा की ओर सीधा इशारा करता है जो हमारी व्यवस्थागत कमियां और दिशाहीनता के कारण अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से वंचित रह गई है।

जब किसी विकासशील देश के करोड़ों युवा न तो भविष्य को संभालने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और न कोई नया हुनर सीख रहे हैं, तो यह स्थिति एक गहरे सामाजिक और आर्थिक संकट की आहट होती है। युवावस्था वह पड़रुख, जिनमें ईशान की चपलतावस्था, कुछ नया सीखने की जलक और शारीरिक ऊर्जा अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है। यह इस अर्थ में ऊर्जा की सही दिशा और अवसर न मिले, तो यह लाना, भटकाना और अंततः गहरी निराशा में बदल जाती है। एक निष्क्रिय युवा केवल अपने परिवार पर आर्थिक बोझ ही नहीं बनाता, बल्कि वह धीरे-धीरे हीन भावना का शिकार होकर समाज की मुख्यधारा से कटने लगता है। इससे पूरे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की रफ्तार व्यापक रूप से बाधित होती है।

इस संकट का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि निष्क्रिय युवाओं में से लगभग आठवां फीसद हिस्सा युवावृत्ति और महिलाओं में है, जो केवल घरलू जिम्मेदारियों की चहारीदार और सामाजिक बंधनों में उलझ कर रह गई हैं। हमारे सामाजिक ताने-बाने में घर-परिवार को देखरेख, बच्चों और बुजुर्गों की सेवा का भार मुख्य रूप से महिलाओं पर ही डाल दिया जाता है। इसके कारण वे अपने करिअर, उच्च शिक्षा या कोशल विकास के अवसरों से पूरी तरह कट जाती हैं। जब देश की आधी आबादी को घर की दहलीज के भीतर सीमित कर उसे मुख्यधारा की आर्थिक उत्पादकता से दूर कर दिया जाएगा, तो कोई भी राष्ट्र अपनी पूरी क्षमता के साथ विकास की वैश्विक ओडिसी में कैसे आगे बढ़ सकता है? महिलाओं को इस सामाजिक और आर्थिक चक्रव्यूह से बाहर निकालने और उनके हाथों में हुनर दिए बिना सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करना पूरी तरह बेवानी है।

आज हर साल लाखों युवा स्वतक की डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब वे नौकरी की तलाश में वास्तविक रोजगार बाजार में उतरते हैं,



तब उन्हें पता चलता है कि उनकी डिग्री और उद्योगों की वास्तविक मांग के बीच कितनी बड़ी खाई है। रिपोर्ट के अनुसार केवल सवा आठ फीसद स्वतक ही ऐसे हैं जिन्हें उनकी शैक्षणिक योग्यता और डिग्री के अनुरूप कार्य मिल पा रहा है। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि हमारे अधिकांश

केवल डिग्रीयों बांटने से देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, इसके लिए युवाओं को व्यावहारिक कोशल से जोड़ना होगा। नीति आयोग ने इस दिशा में दोष दिखाने की दूर करने के लिए स्कूली और उच्च शिक्षा में बुनियादी बदलावों की वकालत की है। सबसे पहली जख्मत यह है कि कोशल विकास को कालेज स्तर तक टालने के बजाय स्कूली शिक्षा से ही अधिवार्य रूप से जोड़ा जाए। जब बच्चा छोटा होता है, तभी से उसके मन में यह बात बैठेडाली जानी चाहिए कि अपने हाथों से काम करना या कोई हुनर सीखना कोई छोटा काम नहीं है। सबसे पहली जख्मत यह है कि जब बच्चे विद्यापीठ प्रवेश करते हैं, तभी से उनके मन में यह बात बैठेडाली जानी चाहिए कि अपने हाथों से काम करना या कोई हुनर सीखना कोई छोटा काम नहीं है। सबसे पहली जख्मत यह है कि जब बच्चे विद्यापीठ प्रवेश करते हैं, तभी से उनके मन में यह बात बैठेडाली जानी चाहिए कि अपने हाथों से काम करना या कोई हुनर सीखना कोई छोटा काम नहीं है। सबसे पहली जख्मत यह है कि जब बच्चे विद्यापीठ प्रवेश करते हैं, तभी से उनके मन में यह बात बैठेडाली जानी चाहिए कि अपने हाथों से काम करना या कोई हुनर सीखना कोई छोटा काम नहीं है।

शिक्षा संस्थान अब केवल ऐसी फैक्टरी बन कर रह गए हैं जो हर साल डिग्रीयों तो थोक में बांट रहे हैं, लेकिन विद्यापीठ के हाथों में वह व्यावहारिक

चंचल मन की गंभीरता

मुकेश पोखरी

बचपन से ही हम धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकों में पढ़ते हैं और पुस्तकों तथा घर के बड़े-बुजुर्गों से सुने आते हैं कि हमारा मन एक चंचल पक्षी है। यह कभी भी एक जाह रश्मि हो कर नहीं रहता। इसके अलावा, यह बात भी पूरी तरह सच है कि हमारे मन पर हमारे परिवार, शिक्षा और समाज के वातावरण का बेध प्रभाव पड़ता है। पहले हमारी बाल्यता बहुत अधिक सुख की थी, क्योंकि हम आधुनिक सभ्यता से परे, वैज्ञानिक संसार का पानों के सीमा पर वाले युग में रहते थे। हम अपने मन में उठ रहे विचारों को कुछ लोक-तन्त्र, कुछ पारिवारिक संस्कारों और कुछ परम्परा विचारों की कभी के कारण किसी दूररे के सामने प्रकट करने में हिचकिचाते थे। ऐसे में अक्सर हम अपने बात अपने दिल में रख लेते थे और बहुत बार फूँकरकर सभाषा ही देखा करते थे। वैसे हमारे पूर्वज अनेक उदाहरणों, लोक कथाओं, गीतों और फलतः कहानियों के माध्यम से बहुत बार हमें कुछ संदेश देने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन उनकी बातों की सीमित साधन, आगे बढ़ाकर सामने और जन्मे में कभी होने के कारण कठिन राली पर चलने से हम आमतौर पर दूर हो रहे थे।

ऐसा भी नहीं है कि पहले सभी लोग डरपोक प्रवृत्ति के हूआ करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शाहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मुकेश रवीन्द्रनाथ टाकुर, राजा राममोहन राय, मौलाना अब्दुल कलाम आदय, त्यागी विवेकानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे अनेक महापुरुषों ने अपने-अपने विचारों को दुनिया के समक्ष रखा। धीरे-धीरे ही इसी, लेकिन देश के अनेक निवासी अनेक वातावरण पर चलने लगे और इस मशाल की रोशनी को दूर-दूर तक फलिते, व्यक्तिगत और राष्ट्र निर्माण में अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान देने लगे आए। आज बनाते के बीच से भी ऐसे लोग निकले, जिन्होंने पिछले और आजादी के मूल्यों के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। अज्ञानता, माया, कुरीतियों आदि की नकारने और निर्यात भाव से शराभ, सेवा और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपने चरम मन की इनके द्वारा गंभीरता की ओर अग्रसर किया गया। नतीजतन, हमारे देश से अनेक अर्थ और हमने अपने देश के लिए आजादी प्राप्त की। देश में व्याप्त दुरावस्था, कुरीतियों की हदसे और समाज के क्रम से उन्नत होने विकास में भी वही स्वतंत्रता सेनानियों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, अर्थशास्त्रियों, चिकित्सकों, विधि विशेषज्ञों आदि सभी वर्गों ने एकजुट होकर कार्य किया। यह स्थिर दिमाग और अपने भीतर बसे साहस के साथ सामने

दुनिया मेरे आगे

ज के अधिकांश युवाओं की यह आदत बन गई है कि इस दुनिया से खुल कर बहस करो, अपने हक के लिए लड़ो। वैश्विक ये आदर्श जीवन-मूल्य हैं, लेकिन ऐसे में मन को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। ये इस बात को नई संस्कार पा रहे हैं कि जब मन अपाठी इच्छानुसार उड़ान भरता है, तब बहुत बुरा उदाहरण लेने से रोक्ता भी है।

आज के अधिकांश युवाओं की यह आदत बन गई है कि इस दुनिया से खुल कर बहस करो, अपने हक के लिए लड़ो। वैश्विक ये आदर्श जीवन-मूल्य हैं, लेकिन ऐसे में मन को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। ये इस बात को नई संस्कार पा रहे हैं कि जब मन अपाठी इच्छानुसार उड़ान भरता है, तब बहुत बुरा उदाहरण लेने से रोक्ता भी है।

इस आधुनिक संसार युग में हमारा मन अपने आल-पाव ही नहीं, देश-विदेश के वातावरण से भी प्रभावित हो रहा है। भले ही, पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों और अनेक अग्रगण्य बुद्धिजीवियों को मुख्यधारा से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन फिर भी उनकी लेखनी और वाणी पर ध्यान दिया जाए, तो अनेक प्रकार की आधुनिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि वर्तमान में पूरे विश्व पर नरक डाला जाए तो हम पाते हैं कि चारों ओर युद्ध का माहौल है। इस युद्ध से बोझी-सी समाज मिल सकती है, लेकिन यह अपाव फिर किसी हद तक से रोक्ता भी है। इसी तरह, युद्ध तो हमेशा होता ही रहा और विनाश का कारण भी। ऐसे में अगर कूटनीति बनाते समय चंचल मन को गंभीरता देना की जाए, तो युद्ध और विनाश को हमला के लिए रोकना जा सकता है। यह भी तय है कि युवा पीढ़ी के साथ ही किसी भी देश के आम निवासी हमेशा युद्ध के खिलाफ हैं और मानवीयते के लक्ष्यों को पूरा करने में भी वही युवा युद्ध बचाने हैं। बल्कि सच यह है कि युद्ध अपने लक्ष्यों को गलत राह की ओर धकेलते हैं और ऐसे में युवा पीढ़ी अपने लक्ष्यों से भटक भी जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी प्रकार के निर्णय को लागू करने से पूर्व उसे मानवीय दृष्टिकोण के तारजू पर तीला जाए और फिर लक्ष्य निर्धारित किए जाएं।

आतंक को शह

पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर गंभीरता भी विविध हैं। जित मरूत अजबत को दुनिया वनी से आतंकी सरना के रूप में पहचानते हैं, उनी पर पाकिस्तान ने इनम रलि बड़ कर 70 लाख रुपए करे भी। माने कोई बड़ा अजबत पकड़ नहीं जा रहा, बल्कि सरकारी ताली की रलि बड़ाई जा रही है। सवाल यह है कि जित विचारों का संगठन 'जैश-ए-मोहम्मद' आतंकवाद की दुनिया में अकलवत है, उसे पकड़ने के लिए पाकिस्तान को इनम बड़ने की जरूरत वनी पड़ी? संयुक्त राष्ट्र अजबत को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर चुका है और 'जैश-ए-मोहम्मद' भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के चपरे में है। इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार है कि अजबत अमानिमतान में छिप है। कभी उनकी तलाश का हिडिग पीछा है और अब उस पर इनम बड़ कर दुनिया को बाना बाना है कि बंदीह, हम तो आतंकवाद के खिलाफ कितने गंभीर हैं। सवाल केवल इतना है कि दुनिया इस अधिनत पर तर्किया बजाय या पूर्व उदा कर अस्तो पकड़ना देती? पाकिस्तान को है कि अतंती सूची भी इसी पकड़ना का हिस्सा दिखाई देती है। सूची में कई ऐसे नाम शामिल हैं, जिनका संबंध भारत में हुए आतंकी हमलों से जुड़ा रहा है।

- विमर्ति नुपयसा, दिल्ली

नाकामी का सिरा

'हिंसा की पीड़ा' (संस्करण, 19 विमर्ति) पाकिस्तान की विविध हैं। जित मरूत अजबत को दुनिया वनी से आतंकी सरना के रूप में पहचानते हैं, उनी पर पाकिस्तान ने इनम रलि बड़ कर 70 लाख रुपए करे भी। माने कोई बड़ा अजबत पकड़ नहीं जा रहा, बल्कि सरकारी ताली की रलि बड़ाई जा रही है। सवाल यह है कि जित विचारों का संगठन 'जैश-ए-मोहम्मद' आतंकवाद की दुनिया में अकलवत है, उसे पकड़ने के लिए पाकिस्तान को इनम बड़ने की जरूरत वनी पड़ी? संयुक्त राष्ट्र अजबत को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर चुका है और 'जैश-ए-मोहम्मद' भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के चपरे में है। इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार है कि अजबत अमानिमतान में छिप है। कभी उनकी तलाश का हिडिग पीछा है और अब उस पर इनम बड़ कर दुनिया को बाना बाना है कि बंदीह, हम तो आतंकवाद के खिलाफ कितने गंभीर हैं। सवाल केवल इतना है कि दुनिया इस अधिनत पर तर्किया बजाय या पूर्व उदा कर अस्तो पकड़ना देती? पाकिस्तान को है कि अतंती सूची भी इसी पकड़ना का हिस्सा दिखाई देती है। सूची में कई ऐसे नाम शामिल हैं, जिनका संबंध भारत में हुए आतंकी हमलों से जुड़ा रहा है।

- विमर्ति नुपयसा, दिल्ली

नकाामी का सिरा

'हिंसा की पीड़ा' (संस्करण, 19 विमर्ति) पाकिस्तान की विविध हैं। जित मरूत अजबत को दुनिया वनी से आतंकी सरना के रूप में पहचानते हैं, उनी पर पाकिस्तान ने इनम रलि बड़ कर 70 लाख रुपए करे भी। माने कोई बड़ा अजबत पकड़ नहीं जा रहा, बल्कि सरकारी ताली की रलि बड़ाई जा रही है। सवाल यह है कि जित विचारों का संगठन 'जैश-ए-मोहम्मद' आतंकवाद की दुनिया में अकलवत है, उसे पकड़ने के लिए पाकिस्तान को इनम बड़ने की जरूरत वनी पड़ी? संयुक्त राष्ट्र अजबत को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर चुका है और 'जैश-ए-मोहम्मद' भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के चपरे में है। इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार है कि अजबत अमानिमतान में छिप है। कभी उनकी तलाश का हिडिग पीछा है और अब उस पर इनम बड़ कर दुनिया को बाना बाना है कि बंदीह, हम तो आतंकवाद के खिलाफ कितने गंभीर हैं। सवाल केवल इतना है कि दुनिया इस अधिनत पर तर्किया बजाय या पूर्व उदा कर अस्तो पकड़ना देती? पाकिस्तान को है कि अतंती सूची भी इसी पकड़ना का हिस्सा दिखाई देती है। सूची में कई ऐसे नाम शामिल हैं, जिनका संबंध भारत में हुए आतंकी हमलों से जुड़ा रहा है।

- विमर्ति नुपयसा, दिल्ली

उपभोक्ता पर बोझ

भारत में डिजिटल क्रांति का पर्याय बन चुका खुशीआ अब नए विचार बुरीआ की ओर है। दो हजार रुपए से अधिक के व्यापारिक लेन-देन पर 0.4 फीसद सेवा शुल्क लगाने का फैसला नीतिगत स्तर पर भले भी बैकै और 'फिनटेक' कंपनियों को आधुनिकीकरण के लिए किया गया हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसके परिणाम सुखद नहीं दिखते। कहा गया है कि इसका सीधा बोझ व्यापारियों पर पड़ेगा और ग्राहकों को कुछ नहीं देना होगा, लेकिन बाजार

एआइ के जोखिम

एक समय या जब दुनिया में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधे युद्ध चल रहा था। उस समय दोनों देश सीधे युद्ध करने के बजाय हथियार, अतिश और तकनीक के क्षेत्र में प्रतियोगिता से आम निवासी को जोखिम देते थे। आज समय बदल गया है और प्रतियोगिता एक ऐसा बड़ा सामने आया है कि दुनिया भर में। पढ़ाई, स्वास्थ्य, कृति, उद्योग, साइबर सुरक्षा और यहां तक कि खा के क्षेत्र में भी इसका दुरुस्तेमाल बढ़ रहा है। इसी वजह से दुनिया के बड़े देश उदाहरण के लिए अमेरिका ने जोखिम को कम करने के लिए एआइ को लेकर प्रतियोगिता सारसे जागरूकता बढ़ा चुकी है। अमेरिका एक तकनीक नहीं है, बल्कि इसे भविष्य की आर्थिक और रणनीतिक ताकत के रूप में भी देखा जा रहा है। मगर एआइ की यह चीज अपने साथ कुछ निहित है। लेकर आती है। उनका समाधान भी जरूरी है।

- अकश कुमार राय, दार्जिला

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

8	4	7	5	3	2	1	6	9
2	6	5	8	9	1	7	3	4
9	3	1	4	6	7	8	5	2
3	7	4	2	8	9	5	1	6
6	2	9	7	1	5	4	8	3
1	5	8	6	4	3	2	9	7
7	9	2	1	5	6	3	4	8
5	8	6	3	2	4	9	7	1
4	1	3	9	7	8	6	2	5



आदिवासी कल्याण विभागाची उदासीनता

देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीतले कातकरी समाजाचे हुतात्मा नाथ्या महापुरूषांचे नाव दिलेल्या या वसतिगृहाला शासनाच्या आदिवासी कल्याण विभागाने मात्र अजून कुठल्याही प्रकारचे मदत केलेली नाही. मुंबईची विश्वस्त संस्था, काही लोकप्रतिनिधी, डॉक्टर, वकील इत्यादींच्या अर्जांसाठीही वसतिगृहाची सध्याची इमारत उभी राहिली आहे. दरमहा सुमारे दीड लाख रुपये खर्ची अशा देणग्यांमधूनच भागवला जातो.

सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकार्यांनी शिफारस करूनही विभागाने सहाय्याबाबत उदासीनताच दाखवली आहे. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांसाठी मिळून आदिवासी कल्याण विभागाने कार्यालय रायगड जिल्ह्यातल्या पेण येथे आहे. तिथले अधिकारी जमिनीतले अन्य जिल्ह्यांमध्ये जाऊन तिथल्या आदिवासी समाजाचे प्रश्न सोडवतात.



वानरमारे समाजाच्या शोषणमुक्तीसाठी...

‘हे वानर मारून खातात’, ‘यांच्या अंगाला वास येतो’ असे म्हणून ज्यांना सरकारी कार्यालयात उमंही केले जात नसे, ज्यांच्या मुलांना शाळेतही एका कोपऱ्यात बसावे लागत असे, त्या समाजातल्या मुलांचे मरिच्य घडवण्याचा, त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ‘शोषित मुक्ती अभियान’ करत आहे. एका वापरात नसलेल्या गोठ्यातून सुरू झालेले या संस्थेचे काम आता बरंच विस्तारले आहे...

को कणातल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला उदय आई हा एक पदवीधर तरुण. कुडाळ तालुक्यातल्या कुसगावचा. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर तो नोकरीच्या शोधात मुंबईला गेला. तिथं रायगड जिल्ह्यात कातकरी आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी कार्यरत असलेल्या एका स्वयंसेवी संस्थेत काम करू लागला. अनुक्रमेण तो नावकडे जात असे तेव्हा त्याच्या लक्षात आले, की आपल्याही जिल्ह्यात हा समाज बऱ्यापैकी आहे. पण रायगड-रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या आदिवासींच्या खूपच मागासलेला आहे. ते सगळे वेढाबगर होते. सावकार, जमीनदार, लक्षाव व्यापारी अशा कोणत्या ना कोणत्या तरी दावणीला पिड्यानपिड्या बांधलेले. या कातकरी समाजाला लोक ‘वानरमारे’ म्हणत. कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या अजूनच्या बागांची माकडांपासून नासधूस रोखण्यासाठी त्यांना ठेवले जात असे. पण जेवण, मजुरी वगैरे काही नाही. मग ते माकडांचाच मारून त्यांचे मांस खात असत. म्हणून ते वानरमारे !



संस्थेपर्यंत कसे जाणू ?

मुंबई-गोवा महामार्गावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ओरोस येथून सुमारे आठ किलोमीटर अंतरावर साईंस घडामोडी वेताळ बाबाई या गावी जाण्यासाठी फाटा आहे. तेथे या संस्थेचे वसतिगृह आहे.

शोषित मुक्ती अभियान हुमरमळ

Shoshit Mukti Abhiyan Humarmal
या नावाने धनदेश काढावा. धनदेशामागे किंवा त्याबरोबर देणगीदारांना आपले संपूर्ण नाव, पत्ता, दूरध्वनी तसेच क्षमगणकी क्रमांक लिहावा. संस्था ८० ची करवस्तव पात्र आहे.

ऑनलाईन देणगीसाठी तपशील

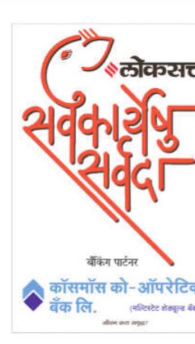
- बँकेचे नाव : द कॉन्सॉस सहकारी बँक, शाहूपूर, कोल्हापूर
- बालू खाते क्रमांक : ८८८९००९०९२२८९
- आयएफएससी : सीओएससी ०००००८९

पहिल्या वर्षी २२ मुलांपासून सुरू झालेल्या या वसतिगृहातल्या मुलांची संख्या आता ९२ पर्यंत पोहोचली आहे. त्यापैकी ४६ मुली आहेत. पहिलीलासून बारावीपर्यंतच्या मुला-मुलींचा यात समावेश आहे. यात दोघे अकरावी तर तिघेजण बारावीपर्यंत पोहोचले आहेत.

पहिल्या वर्षी २२ मुलांपासून सुरू झालेल्या या वसतिगृहातल्या मुलांची संख्या आता ९२ पर्यंत पोहोचली आहे. त्यापैकी ४६ मुली आहेत. पहिलीलासून बारावीपर्यंतच्या मुला-मुलींचा यात समावेश आहे. यात दोघे अकरावी तर तिघेजण बारावीपर्यंत पोहोचले आहेत.

रेषान काई आणि मतदार काई मिळवून देण्याचे काम हाती घेतले. कारण त्याशिवाय त्यांना आदिवासी जमातींना मिळणाऱ्या अंत्योदय किंवा इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळणं शक्य नव्हतं. शिवाय सर्वजण भूमीहीन. सुरुवातीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तर जिल्ह्यात आदिवासी नसल्याचाच दावा केला. त्यामुळे घरांसाठी सरकारी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची जमीन मिळणं दुर्वापर. पण तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणे यांनी या प्रश्नामध्ये सुरू करण्याची मागणी त्यांनी आदिवासी कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे केली. पण विभागाने स्वतःच घेतली नाही. अखेर २०१५ मध्ये उदयचे पुढाकार घेऊन ‘नाथ्या महापुरूषांसाठी’ स्थापन केले. या योजनेसाठी सुरुवातीला त्यांच्या मैत्रिणींच्या बडिलींनी वापरून नसलेल्या गोठ्याची जागा त्याला दिली. तिथे थोडी डागडुजी करून, सौचाल्य-

सुरुवातीला अंगाला वास येतो म्हणून इतर मुलं त्यांना बाजूला बसवला जात. या मुलांमध्ये तंबाखू खाण्याचे प्रमाण बरंच असतं. काही आई-व्यापांनी तर पाच हजार रुपये घेऊन आपल्या मुलांना मॅगझीनला विकल्याची प्रकार पडले होते ! उदयने दिलेल्या माहितीच्या आधारे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक रवींद्र शिंदे यांनी २०१४ मध्ये एका रात्री छापे घालून अशी २२ मुलं मॅगझीनला तावडीतून सोडवली होती. या मुलांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्वतंत्र आराम शाळा, वसतिगृह सुरू करण्याची मागणी त्यांनी आदिवासी कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे केली. पण विभागाने स्वतःच घेतली नाही. अखेर २०१५ मध्ये उदयचे पुढाकार घेऊन ‘नाथ्या महापुरूषांसाठी’ स्थापन केले. या योजनेसाठी सुरुवातीला त्यांच्या मैत्रिणींच्या बडिलींनी वापरून नसलेल्या गोठ्याची जागा त्याला दिली. तिथे थोडी डागडुजी करून, सौचाल्य-



बाथरूम बांधून वसतिगृह सुरू झालं. पहिल्या वर्षी २२ मुलं आली. पण असे राहण्याची सवय नसल्यामुळे मुले टिपत नव्हतं. काहीजण रात्री झडून कुठल्या तरी जवळच्या वस्तीवर जात. त्यांची पाचपैकीही लक्षात घेता ती कुठे गेली असतील, याचा अंदाज बांधून उदय व त्याचे सहकारी त्यांना शोधून पुन्हा वसतिगृहात आणत. एकाद तर वसतिगृहात राहिलेली तीन मुलं पळून ओरोसला एका रेल्वेगाडीमध्ये बसली आणि बेट गोवात मडगावला पोहोचली ! पण संसय आल्याने रेल्वे स्टेशनवरच्या पोलिसांनी त्यांना पकडून ठेवले. दोन दिवस पोलीस ठेराण झालेल्या उदयने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मदतीने त्यांना पुन्हा वसतिगृहात आणले. उदयची पत्नीकाटी आणि कामातले सातत्य पाहून कुडाळ तालुक्यातील वेताळ बाबाई येथील हरिश्चंद्र कर्म यांनी त्यांच्या संस्थेला १८ गुंठे जमीन बक्षीस दिली. त्यावर आता

पक्कं बांधकाम असलेलं वसतिगृह आणि इतर सुविधा उभ्या राहिल्या आहेत. गेल्या सुमारे दहा वर्षांत इथल्या मुलांची संख्या २२ वरून ९२ पर्यंत पोहोचली असून त्यापैकी सुमारे ५० टक्के (४६) मुली आहेत. इयत्ता पहिलीपासून बारावीपर्यंतच्या मुला-मुलींचा वागमये समावेश आहे. त्यापैकी बंधव्या वकी दोघे अकरावी आणि तिघेजण बारावीपर्यंत पोहोचले आहेत. हे सर्वजण जवळच्या प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळांमध्ये जातात आणि संस्थाकाळी वसतिगृहात परत येतात. यापैकी ५० मुलं माध्यमिक, तर ४२ मुलं प्राथमिक शाळांमध्ये आहेत. काही मुलांच्या जाण्या-येण्याचा खर्च संस्थेत शाळा करतात, तर काही मुलांचा खर्च संस्था करते. वसतिगृहात अभ्यासव्यतिरिक्त व्यायाम, खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रमांही होतात. गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात आयोजित विविध साप्ताहिक इथल्या मुला-मुलींनी स्वतःचोपेक्षा जास्त पक्के पटकवले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कातकरी समाजाच्या पुढल्या पिढ्या अतिशक्ति आणि दौर्दंडी राहू नयेत म्हणून उदय त्यांची पत्नी व इतर सहकाऱ्यांसह विविध उपक्रम राबवत आहे. त्यांना पुढ्या प्रवाहात आणण्यासाठी नेटने प्रयत्न करत आहे. आता नव्या पिढीलाही या प्रवाहाची ओढ वाटू लागली आहे. सध्या संस्थेत चारजण मासिक मानधनावर काम करत असून उदयची पत्नी उज्ज्वला महत्वाच्या जबाबदाऱ्या वांभाळत आहे. लवकरच तिने एमएसडब्ल्यू आणि एमएलबीचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. संस्थेचे शिरीष उदयचाचंही काम ती चालते. त्यामुळे एवढ्या कामांमध्ये उजाचा मोठाच हातावर होता. शिवाय, वसतिगृहातल्या मुलांची काळजी घेण्यात तिचे विशेष महत्त्व होते. निवास आणि भोजनावरचाच व्यभिचमत्व विकासामध्ये दृष्टीने वाचनालय, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, क्रीडा साहित्य इत्यादी सुविधा आपण करणाऱ्या उदयचाचं हातमास आहे. त्यासाठी निधीची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. त्यासाठी कोणत्याही अनुदान नसल्याने समाजातल्या उदर हातांच्या आभाराची त्याला प्रतीक्षा आहे.

- सतीश कामत

धनादेश येथे पाठवा... एक हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक रुपयांची देणगी देणाऱ्यांची नावे 'लोकसत्ता'त प्रसिद्ध केली जातील.

मुंबई कार्यालय	महापे कार्यालय	ठाणे कार्यालय	पुणे कार्यालय	नागपूर कार्यालय	दिल्ली कार्यालय
लोकसत्ता, संपादकीय विभाग, मफतलाल सेंटर, सातत मजला, नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०००२९, ०२२-६७४७०२९०	संपादकीय विभाग, प्लॉट नं. ई.एल ९२८, टीटीसी इंड. एरिया, एमआयडीसी, महापे, नवी मुंबई - ४०००७९. ०२२-२०६३९९००	संपादकीय विभाग, प्लॉट नं. १९, तिसरा मजला, होशबानो मॅन्शन, तमिळ शेरुलुम्मा वर, गोविल रोड, नौपाडा (प.ए.) ४०००६२. ०२२-२९३८९९९२२	संपादकीय विभाग, एक्स्प्रेस हाऊस, प्लॉट नं. ९२०४/२/६, शिरोळे रस्ता, पुणे- ४११००४. ०२०-६७४२९९९२९	संपादकीय विभाग, प्लॉट नं. ३८, ओडिसन ट्रेड सेंटर, आंधारा, नागपूर - ४४००९०, ०७९२-२२३०४२९	संपादकीय विभाग, द डिविजन एक्स्प्रेस बिल्डिंग, बी/१, सेक्टर १०, नोएडा- २०१३०९. ०९२०-२०६५९९९००

कुतूहल

खतगट का महत्वाचा ?

बऱ्याचदा अंमिभिया, ल्युकेमियासारख्या आजारांत रक्तातल्या प्लेटलेट्स कमी झाल्या तर किंवा एखाद्या अपघातात खूप जालत रक्तस्राव झाला तर जीव वाचवाय म्हणून आपल्याला दुसऱ्या माणसाचे रक्त दिले जाते. शरीर वगैरे प्लेटलेट्स हा एक मोठा जगार होता, कारण काही वेळा दुसऱ्या माणसाचे रक्त दिल्यावर माणसं मरत असत. यामागे कारण १९०० साली ऑस्ट्रियन डॉक्टर कायल लॅंडस्ट्राइन यांनी शोधले. डॉ. कायल काही रोग्यांमध्ये रक्तस्राव करणारे प्लेटलेट्स नव्हते हे पाहिले. त्यांनी बरेच प्रयोग करून असं सिद्ध केले की, वक्कर पाहता सगळ्या माणसांचे रक्त एकासारखे वाटतं तरी त्यात सुद्धा फरक असतो. त्यामुळे त्यांनी रक्ताचे वेगवेगळे ए. बी, एच, ओ (A, B, AB, O) असे ग्रह केले. कालांतराने डॉ. कायल यांच्या आणखी एक गट लक्षात आला. समजा दोन माणसांचा रक्तगट एकासारखा म्हणजे 'ओ' आहे. तरीही काही वेळा लोकां एकाच रक्त गटात नाही. यावर संशोधन केल्यावर त्यांच्या असे लक्षात आले की, एका माणसाच्या तोंडाच्या पेशींमध्ये 'आरएच (Rh)' नावाचा एक घटक असतो. त्याच्या रक्ताला त्यांनी ओ आरएच पॉझिटिव्ह (O Rh+) असे नाव दिलं आणि दुसऱ्याच्या तोंडाच्या पेशींमध्ये हा घटक नसल्यामुळे त्यांच्या रक्ताला ओ आरएच निगेटिव्ह (O Rh-) म्हटलं. या 'आरएच (Rh)' विभागामुळेही त्यांचे रक्त एकमेकांना वाहत नाही. आता आपल्या रक्ताचे ओ आरएच पॉझिटिव्ह (A Rh+), ए आरएच निगेटिव्ह (A Rh-), बी आरएच पॉझिटिव्ह (B Rh+), बी आरएच निगेटिव्ह (B Rh-), एबी आरएच पॉझिटिव्ह (AB Rh+), एबी आरएच निगेटिव्ह (AB Rh-), ओ आरएच पॉझिटिव्ह (O Rh+) ओ आरएच निगेटिव्ह (O Rh-) असे प्रकार मानले जातात. ओ आरएच निगेटिव्ह या गटाचे रक्त कुणालाही चालत म्हणून या गटाचे रक्त असलेल्या व्यक्तीला 'युनिव्हर्सल डोनर' म्हणतात आणि एबी आरएच पॉझिटिव्ह रक्तगट असलेल्या माणसाला कोणत्याही गटाचे रक्त चालत म्हणून त्याला 'युनिव्हर्सल अक्सेप्टर' म्हणतात. असं असलं तरी प्रत्यक्ष रक्तसंक्रमणापूर्वी रक्तगटाबरोबरच इतर अनेक घटक जुळतात का हे तासलं जातं.

काही कारणांमुळे आपल्याला चुकीचा रक्तगट असलेलं रक्त दिले गेलं तर मात्र त्याचे गंभीर परिणाम होतात. आपल्या शरीरातील रोगप्रतिकारक यंत्रणा रक्तगट वेगळ्या असलेल्या रक्ताला शत्रू समजून तालकाळ नष्ट करू पाहते. त्यामुळे खूप ताप येणं, शस्माने जास होणं, मृत्पिंड निकांती होणं, हृदयविकाराचा इतका गंभीर असे जास होतात. आजची धकाधकीची जीवने चालत आल्याला काहीही रक्ताची गरज पडू शकते. त्यामुळे आपला रक्तगट कुठला आहे हा माहीत असणं अत्यंत गरजेचं आहे.

- डॉ. माधवी ठाकूरदेसाई
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@marvapa.org
संकेतस्थळ : www.marvapa.org

राजवाडे विचारविश्व

स्पाटीकरणात्मक टिपा

चौऱ्यांशीच्या शिलालेखाचे चित्रकथी शैलीतले वर्णन पुढे चालू ठेवत राजवाड्यांनी लिहिले. 'मूळ शिला चौकोनी असून सध्या तिचा उजवेकडील वरचा आणि खालचा असे दोन्ही कोपरे फुटून गेलेले दिसतात. परंतु अखेर पुढील गेल्याचे किंवा वाक्ये दुर्लभाचे काहीच चित्र दिसत नाही तेव्हा कदाचित सध्या जशी शिला दिसत आहे, तशीच ती पूर्वीपासून असले, असेही मानण्याकडे प्रवृत्ति होते... शिलेवरील नव आकारे सारखा आकाराची नाहीत. काही अक्षरांचा व्यास १/८ इंच, काहीचा १/४ इंच, काहीचा १/२ इंच व काहीचा ३/४ इंच आहे. शक ११९५ (इसवी सन १२०३) पासून शक ११९९ (इसवी सन १२०७) पर्यंत पाच वर्षे जसजशी वर्णी आली, तसतशी वर्णीदारांची नावे खोदली गेली. त्यामुळे अक्षरांचा आकार एका सांघीचा राहिला नाही. शिलालेखातील मजकूर नांदीय भाषेवरूनच आपले निरीक्षण नांदीय राजवाड्यांनी पुढे लिहिले. 'प्रस्तावित (संस्कृत) शिरोकाखीरे शिलेवरील बाकी सध्या मजकूर तत्कालीन मराठीत आहे. जनेवरनांनी आपली जनेवरची शक १२१२ (इसवी सन १२२०) मध्ये शिलेवरील, तिच्या आधी १२ पासून १७ वर्षे ही शिला खोदली जात होती म्हणून जनेवरची भाषेची मजकूर ही शिलालेखाची भाषा समजणे रास्त आहे...' या माहितीवरून जनेवरनांसारखे राजवाड्यांनी 'त्या' शिलालेखवरील २२८ ओळींचे जसेच्या तसे शब्दांकन वाचकांमोठे ठेवले आणि त्या ओळींमधील मजकुराचा उमगडा काढा म्हणून तब्बल ४१९ संदर्भपट्टीही लिहिल्या. त्याशिवाय आख्या १३ सध्या समजवले टिपणीही जोडली. त्यांचे महत्त्व समजावे म्हणून दोनच टिपणींचा अर्थ

नमुन्यादाखल उल्लेख करतो. विठ्ठलाच्या स्तुतिपर श्लोकाच्या निमित्ताने राजवाड्यांनी लिहिले. 'ह्यावरून स्पष्ट आहे की शक ११९५चे विठोबाचे आपलाप्रमाणेच असंख्य भक्तजण होते. जनेवरच व नामधेय ह्यांच्यापासून पुढे विठोबाचे माहात्म्य वाढले, असा प्रकार नाही. ११९५ची शिल्लक लहान पोर होते. ते वयात आल्यावर विठोबाच्या असंख्य भक्तजणांवर विरले व आपल्या तपस्तेजाने भक्तशिरोमणित्वा असागण्यत्व पावले. भक्तिमार्गी भक्तजनांची छाप ज्ञानमागी जनेवरवरावर बेतालून बसली...' 'चौऱ्यांशीचा शिल्ल' या नावागे फक्त एखाद्या धनलोकी बडव्याने पसरवलेली अपवा हेच एकमेक कारण नसावे, असे म्हणून धरून राजवाड्यांनी पायाची कारणीष्ट स्पष्ट केली. त्यांनी लिहिले, 'दुसरे कारण असे की, ह्या शिलालेखाच्या प्रारंभी राजाचा जो ११९५चा आकाश आहे, त्यातील १५ अनन्यत वाचकांना ८४ सारखे दिसतात. पाचाचा आकाश अर्धचंद्र उमटल्यामुळे कासारख्या दिसतो व १२व्या शतकातील नवाचा आकाश सध्याच्या आठाराखाली दिसतो. त्यामुळे शक ११९५ची शिल्ल अथवा संक्षेपाने चौऱ्यांशीची शिल्ल असे नाव प्रचलित झाले. या कारणाने बराच सवृत्तिकारण दिसतो. विसरे कारण म्हणजे शिल्लक प्रथम चौऱ्यांशीची वर्णीदारांची नावे खोदली गेली म्हणून दगडाची तशी स्थिति जाली; परंतु एकेदर नावे पाहता ती दुपटीहूनही जास्त आहेत, त्यामुळे हे कारण सवृत्तिकार दिसत नाही'

व्यतिरेक

कवितेला समाजाबद्दल बोलू द्यायचे, पण तिच्यातला गोडवा टिकवायचा ही इतरांना अवघड करताना चालेल, पण काही कवींनी ती जपते. अशा कवींपैकी अनिस उझ-झमर. ते आरामी भाषेत लिहीत, पण त्यांच्या संग्रहांचे बंगाली अनुवाद झाले, अनेक कविता इंग्रजीसह अन्य भाषांतील अनुवादांत झाल्या. कवी, वक्ते आणि साहित्यक्षेत्रातील संघटक अशी त्यांची ओळख होती. त्यांचे निधन रविवारी (२० सप्टेंबर) जालं, तेव्हा ते ७९ वर्षाचे होते. म्हणजे ११४७ या त्यांचा जन्म. पण स्वातंत्र्योत्तर पहिल्या शिल्लकाला तपण कवीचा बोलवाला जसा जण रज्यात/ त्या त्या भाषांत १९७० च्या दशकात होऊ लागला होता, तसे काही आसामात घडले नाही.

अनीस उझ-झमर हे कवी म्हणून १९९९ पर्यंत कुणाला माहीत नव्हते. त्या वर्षी त्यांचा पहिला संग्रह निघाला, तोच 'अज्ञात' अस्थव्याचेही त्यांनी स्वीकारले होते. पुढल्या काळात आसामाकडे समीपाने या संस्थेचे काम त्यांनी केले, तिचे पदाधिकारीही झाले. व्याख्यानांची निमित्ताने फिरले तरीही त्यांची कविता 'अज्ञात' पण जपून जगातकडे पाहत होती. या कवितेला, काश्मीरमध्ये सफरचंद या कविता १५ वर्षांच्या मुलीचे कष्ट दिसत होते, हाडसबोटीच्या भोवतीची पांढर किंवा पिवळट होत चालल्याचेही जाणवत होते. या समग्र कवितेत चालण्याचे 'उदून येणे' आहे, शिवकुवारा किण्किण, 'बासरीच्या लंकेरीसारखे चालणे' आहे, पण कवितेच्या गोळ्याही आहेत, विदोषांपासून आहेत. मराठीत विवाद करंदीकर (१९९९) आणि दिलीप विजे (२००४) यांनी मिळवलेला 'गंगाधर नेशनल पोर्टी अवॉर्ड' हा प्रतिष्ठेचा काव्यपुरस्कार अनिस उझ-झमर यांना २०२२ मध्ये मिळाला. सध्या अजयमोदी पुरस्कारासाठी 'नाझो कोलॉन गेहेर, तुमिरे नेजाना मोंगे नेजान' (नदी कुठे जाते, तुलाही कळते, मला नकळे) या २०१९ मधील पुस्तकाची शिफारस झाली, पण पुरस्काराने हुलकावणी दिली. जयसूर्याने सनमान लाभत भरपूर मिळाले. पण आणखे केवळ आसामात कोणीही नावी- सर्वोच्च अकादमी, सध्या अज्ञात असू पण कवी आहोत- हे मान त्यांनी जपले होते.

अनीस उझ-झमर

अनीस उझ-झमर हे कवी म्हणून १९९९ पर्यंत कुणाला माहीत नव्हते. त्या वर्षी त्यांचा पहिला संग्रह निघाला, तोच 'अज्ञात' अस्थव्याचेही त्यांनी स्वीकारले होते. पुढल्या काळात आसामाकडे समीपाने या संस्थेचे काम त्यांनी केले, तिचे पदाधिकारीही झाले. व्याख्यानांची निमित्ताने फिरले तरीही त्यांची कविता 'अज्ञात' पण जपून जगातकडे पाहत होती. या कवितेला, काश्मीरमध्ये सफरचंद या कविता १५ वर्षांच्या मुलीचे कष्ट दिसत होते, हाडसबोटीच्या भोवतीची पांढर किंवा पिवळट होत चालल्याचेही जाणवत होते. या समग्र कवितेत चालण्याचे 'उदून येणे' आहे, शिवकुवारा किण्किण, 'बासरीच्या लंकेरीसारखे चालणे' आहे, पण कवितेच्या गोळ्याही आहेत, विदोषांपासून आहेत. मराठीत विवाद करंदीकर (१९९९) आणि दिलीप विजे (२००४) यांनी मिळवलेला 'गंगाधर नेशनल पोर्टी अवॉर्ड' हा प्रतिष्ठेचा काव्यपुरस्कार अनिस उझ-झमर यांना २०२२ मध्ये मिळाला. सध्या अजयमोदी पुरस्कारासाठी 'नाझो कोलॉन गेहेर, तुमिरे नेजाना मोंगे नेजान' (नदी कुठे जाते, तुलाही कळते, मला नकळे) या २०१९ मधील पुस्तकाची शिफारस झाली, पण पुरस्काराने हुलकावणी दिली. जयसूर्याने सनमान लाभत भरपूर मिळाले. पण आणखे केवळ आसामात कोणीही नावी- सर्वोच्च अकादमी, सध्या अज्ञात असू पण कवी आहोत- हे मान त्यांनी जपले होते.

- आनंद हार्दिक
ananand47.hardikar@gmail.com

जात सांगणेच बरे...

दर्जेदार संस्था उभारण्यात आलेल्या अपयशाचा परिणाम म्हणजे ‘आयआयटी’सारख्या संस्थांतील विद्यार्थ्यांवरील प्रचंड तणाव; तोही कथित ‘उच्च’वर्णोत्तरांसाठी अधिक जीववेणा...

‘आयआयटी’तील विद्यार्थ्यांच्या आयतलव्हेस जातीय वळण मिळणे हे समस्येचे सुलभीकरण होय. सर्व गंभीर समस्या जात, धर्म आदी चौकटीत डकवायच्या सध्याच्या प्रथेनुसार हे असले तरी त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे साफ दुर्लक्ष होते. तो मुद्दा म्हणजे विद्यार्थ्यांचे असंलला असत्य दबाव. तो निर्माण होण्यात विद्यार्थ्यांचा हात नसतो पण त्यात विद्यार्थ्यांविरावी त्यांचे पालक आणि अध्यापकाही होरपळून निघत असतात. या दबावाचे अस्तित्व ना पालकांस मान्य असते. ना अध्यापकांस, ना सरकारी धुरीणांस. त्यामुळे मूळ समस्येस हातघड घातला जात नाही. तो सोडवली जात नसल्याने, तसे प्रयत्नही होत नसल्याने विद्यार्थी हकनाक बळी पडत राहतात आणि असे काही दुर्दैवी घडवणुका प्रकरणास भलतेच वळण लागते. ‘आयआयटी’तील ताऱ्या घटनेत याच इतिहासाची पुनरावृत्ती दिसून येते.

याच अर्थ या प्रकरणास जातीय अंग नाही; असा अजिबात नाही. ते असले. या नसले. तरी शाहीनांसार कल्याने काहीच साध्य होणार नाही. तरी शाहीनांसार कर्ताशी गणार नाही. कारण यात ज्या विद्यार्थ्यांचा या कल्यात जितकाचप छळस तोंड द्यावे लागले तो कल्यात नाही. त्याच्या अगोरी पालकांच्या आंगी काही विद्यार्थी संघटनांच्या वतीने असा जातीय छळचा आरोप करणेत होते. त्यापुन सर विद्यार्थ्यांच्या काही विद्यार्थ्या मित्रांनी माध्यमंशी बोलताना यामुने जातीय छळ हे कारण असल्याचे साफ नकारले. हे अपाउ उलट. सर विद्यार्थी बुद्धिमान गणता जात होता. त्यामुळे त्याने परीक्षेत ‘कोपी’ केल्याचा आरोप अनेकांस मान्य नाही. ते टीक. पण या विद्यार्थ्यांविरावी कथित आरोप हा कोपी केल्याचा नाही. परीक्षेत त्याने कृत्रिम प्रतेचे (ऑटिफिशल इंटेलिजन्स,

एआय) साहाय्य घेतले ही सदर विद्यार्थ्यांच्या अध्यापकांची तक्रार. यात दोन मुद्दे. पहिला सदर विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमतेचा. त्याबाबत कोणीही कसलाही आक्षेप घेतलेला नाही. दुसरा ‘‘तो बुद्धिमान होता म्हणून निरमर्यादा वनन करणार नाही’’, हा. त्याबाबत समर्थेद अर्सु शकतान. तसेच या मुद्द्याचा प्रतिवाद ज्या अध्यापकांवर ‘कारवाई झाली त्यांच्याही लौकिकांचा दाखला देऊन करता येईल. सदरहू अध्यापकाही पुस्तकांप्राप्त असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे त्यांच्याही इतिहासाचा दाखला देऊन ‘‘इतका चांगला प्राध्यापक ‘असे’ करणार नाही’’, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. सबब वर्तमानातील कथित प्रमादयासी उभय बाजूंनी इतिहासाचे दाखले देण्याने फारसे काही हाती लावता नाही. तेव्हा या आहे तशा वर्तमानास समोरेून भिडायला हवे.

तसे करू गेल्यास विद्यार्थ्यांवरील अतानात तणा आणि दबाव हा मुद्दा प्रमुख. एरवी अगदी शालेय वा सर्वसाधारण महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना भेडसावणान्या वातावरणास ‘आयआयटी’, वैद्यकीय आदी क्षेत्रांतील विद्यार्थ्यांना कित्येक पट अधिक सामोरे जावे लागते. त्यामागील कारण आयआयटी ना वैद्यकीय शाखांतील विद्यार्थी अधिक गुणवान असतात आणि मान्य शाखांतील विद्यार्थी कमअसतात असतात असा समज. मुदतलात हो अशी वर्गावर्गाच अशास्त्रीय आणि पूर्णपणे असमंजसपणाची. कोणत्याही समाजासाठी जसे कुराल अभिनेते, व्यवस्थापक, वैद्यक महत्त्वाचे असतात तितकेच किंवा अधिकच महत्त्वाचे गायक, अभिनेते आणि चित्रकार असतात. आपल्याकडे दुर्दैवाने असे मानले जात नाही. त्यामुळे काही शाखांतील विद्यार्थ्यांवरील दबावाचा

गुणाकार होत जातो. ‘आयआयटी’तील विद्यार्थी हे अशा दबावाचे केंद्रस्थान. प्रमुख पहिल्या... आणि दुसऱ्या... स्वातंत्र्यास इतकी वर्षे उलटली तरी ‘आयआयटी’, काही ‘आयआयएसए’ इतर्या गुणवत्तेच्या आगख्या काही संस्था आध्यापकां उभ्या करता आलेल्या नाहीत. गेल्या काही वर्षांत काही नव्या ‘आयआयटी’ आणि सुरू केल्या खऱ्या. पण तरीही मोठेपण आहे ते आय संस्थांना. त्यामुळे अशा संस्थांत प्रवेश मिळवणे ही हमखास सुखी



प्रतिकूल परिस्थितीतून सामील होणान्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिक पाठिऱ्यासाठी सध्याची संस्थात्मक व्यवस्था प्रतिबंधितचालत नाही...

आणि संपन्न भविष्याची हमी मानली जाते. ‘आयआयटी’तील अशा कोट या अधिक बाष्पिक तनखावर सुरू होणा ‘कॅम्पस फोरेसटर्स’ हे अनेकांचे स्वप्न असते. त्यात गैर काही नाही.

गैर आहे ते अशा इतक्या यशस्वी हमी देणान्या संस्था उभारणीतील आपले देदीयमाना अपयश. या डोळ्यात भरणाऱ्या अपयशाचा तितकाच दुस्य परिणाम म्हणजे ‘आयआयटी’तील विद्यार्थ्यांवर असेलला प्रचंड तणाव. त्यातही हा तणाव कथित ‘उच्च’वर्णोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी

अधिक जीववेणा असतो. याचे कारण त्यांच्यासाठी गुणवत्तेचा अभाव असतो हे अजिबातच नाही. अशा विद्यार्थ्यांची कोटविक, आर्थिक पारवर्भूमी हे यामागील खरे कारण. सुस्थितीतील आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रस्थापित कौटुंबिक वातावरणातील विद्यार्थी हे असा तणाव सहन करण्यास अधिक सज्ज असतात. काही अपयशाचा सामना कराना लागलाच तर वा सवर्ण वर्गीतील विद्यार्थी/ विद्यार्थ्यांस पुरेशी आर्थिक आणि अन्य उस्त असते. ही चैन तुलनेने आढावनामक परिस्थितीतून वेगान्या विद्यार्थ्यांस नसते. अपयश आले, एखादे वर्ष गमावण्याची वेळ आली तर पोटास चिमटा काढून शिवकण्यांना आपल्या पालकांस सामोरे जायचे कसे हा प्रश्न अशा विद्यार्थ्यांसाठी जीवनमरणाचा असतो. तो सोडवण्यास असले तर ‘आयआयटी’ या तत्सम संस्थांत प्रतिकूल परिस्थितीतून सामील होणान्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिक पाठिऱ्यासाठी काही एक संस्थात्मक व्यवस्था हवीच खरी. सध्याची व्यवस्था प्रतिबंधितचालत नाही. मानसिक तणाव, त्रासय आदी आजार पडल्यानंतर मिळणान्या उपचारांसारखे. आजारी पड्याे सवर्ण वर्गातील, यासाठी सावध नाही. ते पुराववे लागेल.

ते नसणे हे दुर्बल घटकांतून या संस्थांत वेगान्या विद्यार्थ्यांस अधिक दुर्बल करणारे असते. हे दौर्बल्य दिसू लागले की जाती-वाद फोफावण्यास मदत मिळते. अलंकेडे हिंदू-मुसलमानांत ज्याप्रमाणे ‘आरण्य’ आणि ‘ते’ असे सरास होऊ लागले आहे त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांही ‘राखीव जागावाले ते’ आणि ‘आरण्य’ असे दुर्भाग होत. वास्तव तपासल्यास तो गैरलागू आहे आणि त्यात

सवर्णांच्या ‘आम्ही श्रेष्ठ’ गंडाचा मोठा वाटा आहे. ‘आयआयटी’ या तत्सम संस्थांत खुल्या प्रवर्गातील आणि राखीव जागांतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत मोठा फरक असतो असे नाही. तरीही खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी स्वतःस श्रेष्ठ मानतात. पण त्यांचे अस्वस्थ कितपत होणे जास्त हानीकारक असते. गुणवत्तेचा मक्ता जणू आपल्याकडेच आहे असे मानणारे हे उच्चवर्गीय ‘आर्थिकदृष्ट्या मागास’ प्रवर्गातील आणि त्याहीपेक्षा सरळ पैसे देऊन उच्च विद्याशाखांत प्रवेश घेणान्या धनदांड्यांच्या मुलाबाळांविषयी मात्र सोयीस्कर मीन वाळताना. इतकेच नव्हे; तर यातीलच काही आर्थिकदृष्ट्या समर्थ तुल्ये स्वतःही या अशा ‘पैसे मोठा, पदव्या घ्या’ या वर्गात कसे शिरता येईल या प्रयत्नात असतात. तेव्हा मुसलमान ही काही आपलोच मक्तेदारी आहे असे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी मानण्याचे कारण नाही आणि इतरांनी कानकोडी विरोधी गर्ज नाही. ते झाल्याचे या खरे नुकसान त्या संस्थेचे होत. आताच्या प्रकरणातील तोच पोळा आहे.

‘आयआयटी’त विद्यार्थ्यांची जात अध्यापक आणि अन्यस सांगितली जात नाही. ‘आयआयटी’तील वास्तव त्याने ते ससे केलेले उलट बरे. कारण त्याला कोणाशी किती संबंधदर्शिलेलेने वागवायचे हे संबंधितस आधीच कळू शकेल. शिकलेले विद्यार्थ्यां तरी आक्षेप घेतल्यावर जातीचे कारण पुढे करण्यापेक्षा पूर्वकल्यान असणे अगदीच वाईट नाही. त्याचेही दुष्परिणाम आहेतच. परंतु यातमितीतून जात हे वास्तव आहे. कितीही शास्त्राव्याच प्रचलत केला तरी ते झालेले जाणारे आहेत. हे सत्यही अंगीकारण्याची सवय सर्वांस होईल.

लोकमानस

आयोगाला वेसण हवारीच !

‘कमिशन’ की ‘ओमिशन’ ? हा अग्लेख (२२ सप्टेंबर) वाचला. परिचय बंगालमध्ये विभागास मानवडकीच्या तीडावर रावकलेली एसआयआर मोमोम ही ममता बॅनर्जी यांच्या मतदारांच्या खचीकरणासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या शाऱ्यावर रावकल्याचे स्पष्ट दिसते. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना शाय्य विचारसरण्यास मतांचे खचीकरण होणे मरजेचे वाटत असेल. त्यामुळेच सत्ताचे न्यायालयाचे आदेश डावलून मुख्य निवडणूक आवुक्तांच्या नेमणुकीचे अधिकार २०२३मध्ये कायद करून स्वतःकडे घेतले गेले. शिवाय त्यांनी कायदाही संकल्प देऊन ममानाी करण्याची मुभाही मिळवून दिली. परिणामी निवडणूक प्रक्रिर्तेत निःसफायांच्या विषयऱ्याड उडत आहेत. २०२३चा कायदा मोडीत काढून निवडणूक आवुक्तांच्या नाकात वेकण घातल्यावरान्या निवडणूक प्रक्रिया निषध होऊच शकणार नाही.

किंवा थोरात, नांशिक

विरोधात काय का घेत नाहीत ?

‘कमिशन’ की ‘ओमिशन’ ? हा अग्लेख वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला एसआयआर मोमोम करणारा पत्रावलीने देताना याबाबतचा स्पष्ट आखाड मगलाना नाही, यमितीक पातळीवर छाननी करताना उडवून काढण्याचा बांधव्य समस्येबाबतच्या प्रश्न उपस्थित होत नाहीत. आयोग ही प्रक्रिया नेमकी कशी पुढे नेणार आहे, याबाबत देश अंधाऱ्यात राहिल. देशातील विरोधी पक्षाही या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीतील समस्या पत्रावलीने मोडण्यात अपयशी ठरले. आज विरोधी पक्ष विखुरलेल्या स्थितीत आणि निकटव. आज त्यांचे एकवृत्ततेणे कायदेशीर आणि सर्वजनिक सभांना उभारण्यात अपयश आले आहे. अशा स्थितीत सत्ताधाऱ्या पक्ष एसआयआर याका स्वतःच्या फायद्यासाठी वार कर घेतल्यास नवल नाही.

पण दमडणूक, ठाणे

त्यापेक्षा खरच प्रयत्न जाणून घ्या ‘तुम्हाळू’त भाजपच्या कर्मिणेचे आढावने हा ‘अन्यथा’ (२२ सप्टेंबर) वाचला. तुळू ही बंट समाजाची भाषा असून हा समाज मंडळूळ, उडणीमध्ये एकवटलेला असला तरीही भाषा संपन्न कर्मिकांमध्ये बोलली जाी कारण याभाषेबाबतमितीत हा समाज सर्व परसलला आहे. परिणामी या निगण्यावळी कर्मिेला लोकांचे प्रम मिळेल. या निमित्त वेळ कर्मिेने भाजपला आवाकडे द्या आहे. असा किमती काढणे उता जास्त वाढते. त्यापेक्षा तितक्या बंड समाजाचे प्रश्न जाणून घेतले तर जास्त पातळीत मिळेल.

माया भाटकर, बाणेर (पुणे)

विश्वास अमेध हरजेचे

‘टाटांचा वारसा जणवत्याच हवा...’ हा लेख (२२ सप्टेंबर) वाचला. ‘टाटा सन्स’ची मालकी रचना ही जागतिक भांडवलशाहीत अत्यंत दुर्मिळ व्यवस्था असून, सर्वोच्च होईलक कंप्नीचे दोन तुर्किया समभाग माध्यम निव्वरस संस्थांकडे असून ते तीस आगेव्या, शिष्टाणे, पोण, उपनिष्ठाक, वैज्ञानिक संशोधन, कला संस्थांकडे. कामांसाठी चळवळा जातो. सर्वोच्च पाठळीवरील मालकी परोपकारासाठी बांधील असून देशासाठी संस्थेचे योगदान अभूतपूर्व आहे. १०० वर्षे जगलेल्या विश्वावर्तमितीचा हा जागतिक विश्वास उठला आहे. आज सरकार, कंपन्या, विद्यापीठे, प्रसारधर्माणे आणि धर्मकांड संस्थांवरिल लोकांचा विश्वास नेमी होत चालला आहे. या पारवर्षीक घडणूक टाटांवरिल विश्वास असाय राहणे मरजेचे आहे.

प्रदीप कर्मकर, ठाणे

नािम अधिक कठोरात हवेत !

‘सायरी किनारा मागांवर तीन विद्यावरील अपवाती मुवू’ ही बातमी (लोकसत्ता- २२ सप्टेंबर) वाचली. भारतात रसव्यवलीत अपवाती मुवूने प्रमाण चित्रण काढले असून ते रोखण्यासाठी कठोर उपपयोगांची गरज आहे. त्यासाठी सर्व सहजानाी वेगवेगळीक संस्थांकडे, बाह्यन सल्लाक पत्रावना देण्याची यमवर्माणी वाढवून ती तुर्कियासाठी ३० वर्षे व चारकाळासाठी ४० वर्षे करण्यात याव. रस्ते अपवातीतून मुलूस वाहत चालवणारे असेल तर याकाविविडध सदीप भुनयण्याचा गुहा दाखल करण्यात याव. अपवाताला जबाबदार वाहन कायमचे जप करावे आणि दोषी आढळलेल्या वाहनचालकांना त्यांच्या बहानाच्या किमतीतला दमरपट दंड आकारण्यात याव. दोषी चालकांचा पत्रावा कायदयाच दंड जात. कितीकी कठोर शिक्षा तितकेच गुन्याचे प्रमाण कमी राहील, अशी आशा.

आशुतोष शेंडे, बोरीवली (मुंबई)

महाराष्ट्र’ अन् व औषध प्रशासने’चे आवुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या लक्षात असे की सलानीची बाटली, सिंजिज, कॅन्डेल इ. वैद्यकीय साहित्यावर काही रुग्णांचेचे अप्रिचंड होत असून अतुक्रुमे २८२२ टक्के, ७७७ टक्के आणि ९५५ टक्के नफा कमवता आहेत (ही लुटमार/ फेकेलोर वंड करणारेचे अधिकार त्यांना नसल्याने त्यांनी केंद्र सरकारला विनंती केली की या ‘वैद्यकीय साहित्या’ बाबत रुग्णांचे, व्यापारी घेत असलेल्या न्यायभार ‘औषध किमती निवंत्रण आदेश- २०१३’ अंतर्गत निवंत्रण आणवे. कारण काही विशिष्ट वैद्यकीय साहित्याच्या बाबतीत फार नफेवारी होत आहे असे केंद्र सरकारच्या औषध-खात्याला वाटले तर ‘औषध किमती निवंत्रण आदेश- २०१३’ अंतर्गत त्यांच्या किमतीवर सारक निवंत्रण आणू शकते. उदा. हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी बसवण्याच्या स्टॅट बाबत सरकारने असे निवंत्रण आणले होते. पण अशी उदाहरणे अपवादात्मक आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय साहित्याच्या बाष्पिकां लाख-लाख कोटी र. विक्रीपैकी फक्त सुमारे तीन टक्के विक्री का किमती-निवंत्रण खाली आहे ! मुंढेचे हे पाऊल स्वागताईत असले तरी हे साहित्य रुग्णांना विकताना विक्रिते हा हॉस्पिटल्स कमवतात असल्याने फक्त व्यापारी न्यायभार निवंत्रण आणण्यात बहलू मुंढे बोलत आहेत. खरे तर ‘वैद्यकीय साहित्य’ व औषध या दोघांच्या बाबत औषध-खात्या व औषध-व्यापारी या दोघांच्याला न्यायभार निवंत्रण आणले पाहिजे. त्यासाठी त्यांच्या किमती सरकारने निवंत्रित करायला हव्या. कारण या बाबतीत सध्या काय व कसे करते आहे ते योजयानात नाहू.

औषधांच्या किमतीवर न्यायभार निवंत्रण लहान घडवणूक बसूची खरेवी करताना शिखला परबडेते तेव्हा आणि परबडेते त्या जगाची वस्तु शाब्दक विकत घेतात. पण औषधांचे तसेच वैद्यकीय साहित्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या खरेदीदारांचा रुग्णाला कसरीतच पर्याय उपलब्ध वसतो. तो हवाबल असतो. आता पैसे नाहीत म्हणून पुढच्या महिन्यात औषध घेऊ किंवा कमी किमतीत दुसऱ्या कंपनीचे औषध मिळते का ते पाहू असे करणाऱ्या परिस्थितीत रुग्ण नसतो. त्यामुळे औषधांच्या किमतीवर सरकारने निवंत्रण देवयानाच हवे. त्याबाबत सामाजिक दबाव सतत बरे रिहलणेने हावी यमितीतल्या शिफारसीस पुस्तकाला गढीला औषधांवर औषध उत्पादन-व्यापारच्या तुलनेत ४० ते १०० टक्के फरकच नफा घेऊन किमतीचे बंधन १९९७ मध्ये सरकारने आणले. ते नेमही लागणान्या काही दरमिळ औषधां पुरवच लागी होते. सुरवात म्हणून हे च्याले पाऊल होते. पण औषध कंपन्यांच्या विरोधातच व १९९० नंतर तर सरकारनेच बाजारवादी धोरणे घ्यावता सुरवात केल्यामुळे ते हळूहळू

निकष कशाकशाचे ? महाराष्ट्रात दुकाळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया अधिक शास्त्रीय, वस्तुनिष्ठ आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी महसूल व वन विभागात २८ जून २०१८ रोजी शासन निर्णय प्रसुत केला. त्या सुधारित निर्णयानुसार दुकाळचे मूल्यमापन केले जावे. यासाठी विविध बाबींचा टप्प्याटप्प्याने विचार केला जातो. पहिल्या टप्प्यात पाऊल आणि कोटऱ्या कालावधीपर्यंत अनिवार्य निव्वरस घ्यायला जातो. दुसऱ्या टप्प्यात पिक्कींची स्थिती, पेराणी क्षेत्र, पिक्कींची स्थिती, आर्द्रता आणि जमिनीवरील सिंधवित निर्मणांचा एकत्रित विचार केला जातो. मध्यम किंवा गंभीर दुकाळालाची शक्यता दिसून आल्यास तिसऱ्या टप्प्यात प्रश्नक्ष क्षेत्रीय पाहणी केली जाते.

पाऊस हाच मुख्य निकष ? पावसासाठी तुट मोजवणारासाठी प्रत्यक्ष आणि सामान्य पावसाची तुलना केली जाते. सामान्य पावसाच्या तुलनेत २० टक्केपर्यंतची तुट सामान्य, २० ते ५९ टक्के तुट गंभीर आणि ६० ते ९९ टक्के तुट अति गंभीर, या स्वरूपात नोंदवली जाते. या शिवाय नार आलवड्यांचा कोटऱ्या कालावधी हा महत्त्वाचा निकष आहे. हलक्या दुकाळाला बसवितो तीन आठवड्यांचा कोटऱ्या कालावधीची विचारत घेतला जातो. जून - जुलैचा प्रत्यक्ष पाऊस सामान्य पावसाच्या ५० टक्केपेक्षा कमी असल्यास, कोटऱ्या कालावधीची अट स्वतंत्रपणे लागू नसली तरीही पहिला टप्पा लागू होऊ शकतो. त्याप्रमाणे जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील प्रत्यक्ष पाऊस त्या कालावधीच्या सामान्य पावसाच्या ५५ टक्केपेक्षा कमी असल्यासही पहिला दुकाळ दिग्नर लागू होऊ शकतो.

वारगळले. ‘औषध-किमतींवर सरकारने सुयोग्य निवंत्रण आणणे’ असा मागीलसाठी २०२३ मध्ये ‘ऑल इंडिया इगू अंकेषन नेटवर्क’ (आयईन) ‘फेड अम्ही अनेकांनी खोचोच आणलेला वाष्पिका दाखल केली. सरकारने कोटीत बरीच चावतकडवली केली. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला इशारा दिला की सरकारने किमती-निवंत्रण आणले नाही तर न्यायालय त्याबाबत आदेश देईल. त्यामुळे २०१३ मध्ये सरकारने ‘राष्ट्रीय औषध योजी’ मधील औषधांवर निवंत्रण आणली. गुणकारी तसेच तुलनेने कमी साइड रफेनिक असणारी सुमारे एक हजार औषधे औषध-शास्त्राच्या पुस्तकात समाविष्ट केली आहेत. त्यापैकी भारतातील ९० टक्के आजारांवर गुणकारी असणान्या ३८४ औषधांचा ‘राष्ट्रीय आवश्यक औषध-यादी’, तर ५० टक्केपर्यंत केला आहे. सरकारने फक्त बरी औषधे किमती-निवंत्रणाखाली आणली आहेत. खर तर सर्व औषधे, सर्व वैद्यकीय साहित्य यावर किमती-निवंत्रण आणले पाहिजे. पेटंट खाली असणान्या मूठभर, नव्या औषधांचा फक्त अपवाद असेल. दुसरे म्हणजे औषधांवर किमती-निवंत्रण

दुकाळ जाहीर करण्याचे निकष काय ?

पेराणी क्षेत्र हा निर्णायक संकेत ?

खरीप हंगामात आंगरंग अक्षर प्रत्यक्ष पेराणी झालेले क्षेत्र सामान्य क्षेत्राच्या तुलनेत ८५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास मध्यम स्वरूपाचा, तर ७५ टक्केपेक्षा कमी झाल्यास गंभीर दुकाळ समजला जातो. रब्बी हंगामात हे निकष डिसेंबर अखेरच्या प्रत्यक्ष पेराणीस लागूले जाताना, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणीत पीक नुकसान ३३ टक्केपेक्षा अधिक आढळल्यास संबंघित गाव दुकाळी म्हणून घोषित होण्यास पात्र ठरू शकते. पीक नुकसान ५० टक्केपेक्षा अधिक असल्यास दुकाळाची तीव्रता गंभीर मानली जाते. दुसऱ्या अण्यानंतर, प्रतिनिधित्व पाहणीतील ३३ टक्केपेक्षा अधिक पीक नुकसान आढळल्यास मध्यम , तर ५० टक्केपेक्षा अधिक नुकसान आढळल्यास गंभीर दुकाळ मानला जातो.

उपमाहारा मदीने खारडामय ?

महाराष्ट्राचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव उपमाहारा देवरा गंभीर जुलै २०१८ मध्ये दुकाळाची शक्यता राहिल्याती अटी अत्यंत कठोर होत्या. देवरा समितीने संविधानातील सुचलेल्या सुलभ निकषांनुसार एमडीसीआय म्हणजे प्रमाणित वस्तुती (पीक) किमतीच्या मदीने उपग्रहाच्या मदीने जमिनीवरील

केंद्र सरकारच्या कृषी आणि सहकार विभागात

२०१६ मध्ये दुकाळ संविदा जाहीर करून दुकाळ जाहीर करण्यासाठीचे निकष निरखित केले होते. महाराष्ट्र सरकारने २०१८ मध्ये त्याआधारे सुधारित शासन निर्णय प्रसुत केला, त्यानुसार राज्यात दुकाळ जाहीर होतो...

पिकांचे आरोम्य, घनता आणि हिरपेपणा मोजून एक शास्त्रीय निकष तयार करण्यात आला आहे. त्यासह व्हीसीआय निकषचे वस्तुती स्थिती निदर्शक, हाही उपग्रह आकडेवारीवर आधारित एक अत्यंत महत्त्वाचा निदर्शक आहे. य्नादारे पिकांच्या सध्याच्या आरोग्याची तुलना मागील अवस्थेच्या (एॅगिहासिटी) वस्तुती व संवित वाढत ध्याविली केली जाते. वस्तुतीशी संबंघित निदर्शक, लावडही खालील क्षेत्र, मनु आर्द्रता आणि जलविषयक निदर्शक, या चार प्रमुख प्रभाव दर्शक निदर्शकांपैकी एक स्थवित दर्शनाण्या तीन

epaper.loksatta.com

Lifetime Free Newspapers Access

Editorials PDF

- English Editorials PDF with International Newspapers Editorials [35-40 pages]
- Hindi Editorials PDF
- Daily Vocabulary PDF

Magazine Channel

National & International
[General & Exam related]

International Newspapers

Newspapers around world.
Asian, European & American

Hindi Newspapers

- 1) दैनिक जागरण
- 2) जनसत्ता
- 3) हरिभूमि
- 4) हिंदुस्तान

Indian Newspapers Channel

1. The Indian Express

2. The Hindu

3. Business Line

4. Financial Express

5. Times of India

6. Hindustan Times

7. Economic Times

8. Live Mint

9. Business Standard

